प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

26.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 15:00बजे

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में सभी पात्र पेंशनधारकों को उनकी पेंशन मिलती रहेगी। शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी पात्र व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद न की जाए। उन्होंने कहा कि अब तक 7 लाख 60 हज़ार 7 सौ 72 लाभार्थियों का ई–केवाईसी पूरा किया जा चुका है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की भी समीक्षा की और कहा कि वर्तमान में राज्य के 4 हज़ार एक सौ 31 बच्चे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं।

पुलिस कार्रवाई

दिल्ली और हिमाचल पुलिस के बीच हुए बवाल पर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल पुलिस की कार्रवाई को उचित बता रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने प्रदेश पुलिस की कार्रवाई को गैर–कानूनी करार दिया है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार की किसी भी अपराधी को बचाने की कोई मंशा नहीं है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार किसी दूसरे राज्य में कोई कार्रवाई करने से पहले उस राज्य की पुलिस को सूचित करना जरूरी होता है लेकिन दिल्ली पुलिस ने नियमों का पालन नहीं किया।

दूसरी ओर भाजपा विधायक विनोद कुमार ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सुक्खू सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ए.आई. समिट में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से देश की छवि खराब हुई है।

बिंदल / रणधीर

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि भारत मंडपम में आयोजित ए.आई समिट प्रकरण में जिन लोगों पर भारत की छवि धूमिल करने के गंभीर आरोप हैं, उन्हें सरंक्षण देने के लिए प्रदेश सरकार ने कानून के रखवालों को ही आमने–सामने खड़ा कर दिया है। ऊना में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों को बचाने के लिए अगर सरकार पुलिस बलों को टकराव की स्थिति में लाए तो इससे बड़ा संवैधानिक संकट कुछ नहीं हो सकता। इस बीच विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश पुलिस द्वारा दिल्ली से आई पुलिस टीम को विधिसम्मत कार्रवाई करने से रोकने और उनके साथ अभद्र व्यवहार किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

नितिन गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा देश के लिए एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। उन्होंने भारत में बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता व्यक्त की। सड़क सुरक्षा पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग पांच लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें करीब एक लाख 80 हजार लोगों की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब प्रदर्शन–उन्मुख नीति अपनाई है, जिसमें बेहतर जवाबदेही और सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय लेखापरीक्षा के बजाय प्रदर्शन लेखापरीक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम राहत योजना का भी जिक्र किया जिसके तहत सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से सात दिनों की अवधि के लिए प्रति पीड़ित एक लाख 50 हजार रुपये तक का नकद उपचार मिलेगा।

होमगार्ड

प्रदेश गृह रक्षा विभाग में होमगार्ड स्वंयसेवकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से अवेदन के साथ नो ड्रग यूज प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। विभाग के अनुसार होमगार्ड राज्य की कानून व्यवस्था आपदा प्रबंधन और अन्य आपात सेवाओं मे अहम भूमिका निभाते है। जिसके लिए युवाओं का शारिरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व नशामुक्त होना जरूरी है। प्रदेश में 7 सौ होमगार्ड स्वंयसेवकों के पद भरे जाने है जिसके लिए 31 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए गए है।

————————————————